RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : शनिवार 25 मई 2024 वर्ष 06 अंक 37 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक रोकठोक लेखनी

खबरें बे-रोकटोक

4 जून के बाद महाराष्ट्र पुलिस में बड़े फेरबदल...

Page - 2

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

महाराष्ट्र विधान परिषद की चार सीट पर 26 जून को चुनाव

1 जुलाई को मतगणना...

मुंबई : निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र विधान परिषद की चार सीट के लिए चुनाव 26 जून को होगा। आयोग ने एक विज्ञप्ति में कहा कि मतगणना एक जुलाई को होगी। मुंबई, कोंकण और नासिक शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल सात जुलाई को समाप्त होने वाला है। मुंबई शिक्षक और मुंबई स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व वर्तमान में क्रमशः कपिल पाटिल (लोक भारती) और विलास पोटनीस (शिवसेना-यूबीटी) कर रहे हैं।

कोंकण संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भाजपा के निरंजन डावखरे कर रहे हैं, जबकि नासिक संभाग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किशोर दराडे कर रहे हैं।

आयोग ने पहले 10 जून को चुनाव कराने की योजना बनाई थी। लेकिन गर्मी की छुट्टियों के बाद ये चुनाव कराने के शिक्षकों के अनुरोध पर आयोग ने अपना फैसला बदल दिया। विज्ञप्ति के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख सात जून होगी, जबकि मतपत्रों की जांच 10 जून को की जाएगी तथा नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जून है। महाराष्ट्र विधान परिषद 78 सदस्यीय सदन है।

'चार जून को चुनाव परिणाम आने के बाद मुंबई में शराब बिक्री की अनुमति'

हाईकोर्ट ने की अहम टिप्पणी

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने चार जून के बाद मुंबई में शराब की बिक्री की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति एनआर बोरकर और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेसन की अवकाश पीठ ने शुक्रवार को कहा कि होटल, रेस्तरां, बार और परमिट रूम में शराब की बिक्री पर शहर कलेक्टर के लगाए गए प्रतिबंध मुंबई शहर में चुनाव के नतीजे घोषित होने पर प्रभावी नहीं होगा।

अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योति चव्हाण ने पीठ को सूचित किया कि मुंबई जिला उपनगरीय के कलेक्टर ने पहले ही एक पत्र जारी कर 4 जून को ड्राइ डे घोषित करने वाली पिछली अधिसूचना को संशोधित कर दिया

है। हालांकि, मुंबई शहर कलेक्टर की ओर से ऐसा कोई संशोधन जारी नहीं किया गया था। इसके बाद पीठ ने चुटकी लेते हुए कहा कि शहर के उपनगरों में लोग परिणाम घोषित होने के बाद शराब पी सकते हैं, लेकिन शहर के लोग ऐसा नहीं कर सकते।

इस पर उच्च न्यायालय ने कहा, आइए इस पर काम करें। कुछ तो समानता होनी चाहिए। अदालत इंडियन होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन (एएचएआर) की दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इसमें मुंबई शहर और मुंबई जिला उपनगर के कलेक्टरों की ओर से 4 जून को पूरे दिन ड्राई डे घोषित करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिकाओं में कहा गया है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद शराब की बिक्री की अनुमति दी जानी चाहिए।

महाराष्ट्र में भीषण जल संकट !

सूखे के हालत से किसान त्रस्त... लोगों में भारी नाराजगी

मुंबई: महाराष्ट्र के मराठवाडा समेत राज्य के जिलों में लोगों को भीषण जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी रिपोर्ट है कि संभाजी नगर के डैम में सिर्फ 9.73 प्रतिशत जल बचा है। वहीं राज्य के सभी प्रमुख डैम में सिर्फ 24.03 फीसदी पानी बचा है। लोगों व किसानों को समय से मदद नहीं मिल पाने के कारण भारी नाराजगी है। कई गावों में पानी के लिए भारी गर्मी के बीच कई किलोमीटर का पैदल सफर करना पड़ रहा है। हालांकि टैंकरों की मदद से पानी आपूर्ति कर लोगों की मदद करने का प्रयास किया जा रहा है।

22 मई के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कुल दो हजार 994 बांधों 24.03 प्रतिशत जल है। जबकि पिछले साल इसी दिन राज्य के बांधों में 34.36 प्रतिशत जल थे। सबसे कम जल संचय छत्रपति संभाजी नगर

में दर्ज की गई है। यहां के कुल 920 बांधों और जलाशय में सिर्फ 9.73 प्रतिशत पानी पानी बचा है।

10 हजार से ज्यादा गांव सूखे की चपेट में

इस साल 10 हजार से ज्यादा गांव सूखे की चपेट में हैं। जबकि मई महीने के दौरान पिछले साल सिर्फ 1,108 गांव सूखे की चपेट में हैं। इससे सूखे के भीषण हालात का जायजा आसानी से लगाया जा सकता है।

3 हजार से ज्यादा टैंकरों की मदद से पानी की आपूर्ति

वर्तमान में करीब 3658 टैंकरों की मदद से पानी की आपूर्ति की जा रही है। इनमें से 1812 टैंकरों का इस्तेमाल मराठवाडा में पानी की आपूर्ति के लिए किया जा रहा है। वहीं छत्रपति संभाजी नगर में 698 टैंकरों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

भीषण सूखे की वजह से किसानों के फसल बर्बाद हो गए हैं। सोलापुर में किसानों ने पानी की कमी के कारण अपने केलों के फसल को काट दिया है। राज्य के अन्य जिलों में भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं।

राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे ने भीषण जल संकट व सूखे की हालात को देखते हुए चुनाव आयोग से आचार संहिता में ढील देने की मांग की है। महाराष्ट्र में लोकसभा की सभी सीटों के चुनाव खत्म हो गए हैं। लेकिन अन्य राज्यों में अभी कुछ चरण के चुनाव से बाकी हैं। हालांकि महाराष्ट्र के हालात को देखते हुए आचार संहिता में ढील देने की मांग की गई है। ताकि जरूरतमंद लोगों की पूरी तरह से मदद की जा सके।

जारी है हादसों का सिलसिला!

एक और नाव डूबी, सिंधुदुर्ग में बर्फ ले जा रही नाव पलट गई; दो की मौत, दो लापता

सिंधुदुर्ग: राज्य में पिछले तीन दिनों में अलग-अलग घटनाओं में 18 लोगों के डूबने की घटना तो ताजा है ही, अब नाव पलटने की एक और घटना सामने आ रही है. सिंधुदुर्ग के वेंगुर्ले बंदरगाह में एक नाव पलटने की दुर्भाग्यपूर्ण खबर सामने आई है. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है और दो लोग लापता हैं. लापता लोगों की तलाश जारी है. अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक, रात में मछली पकड़ने वाली नावों के लिए बर्फ ले जाते समय वेंगुर्ले बंदरगाह में नाव पलट गई. इस नाव में कुल सात नाविक सवार थे. नाव पलटने के बाद तीन लोग तैरकर किनारे आ गए। जबकि चार लोग लापता थे, उनमें से दो के शव मिल गए हैं और दो लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है।

यह दुर्घटना तब हुई जब रात में सिंधुदुर्ग जिले के वेंगुरला बंदरगाह से

मछुआरों के लिए आवश्यक बर्फ ले जाया जा रहा था। शुरूआती अनुमान यह है कि रात में आए तूफान और तेज हवा के कारण नाव भटक गई। लापता नाविकों में एक रत्नागिरी का जबकि तीन मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। अन्य नावों से नाविकों को बचाने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया। पिछले तीन दिनों में राज्य में अलग-अलग घटनाओं में डूबने से 18 लोगों की मौत हो चुकी है. मंगलवार 21 तारीख को नासिक के इगतपुरी में भावली बांध में पांच लोग डूब गए. इंदापुर के उझानी बांध में यात्रियों से भरी एक नाव डूबने से छह लोगों की मौत हो गई.

संपादकीय...

ओबीसी प्रमाणपत्र 'अवैध'

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में, 2010 के बाद, सभी ओबीसी प्रमाणपत्रों को निरस्त कर दिया है। इस संबंध में सभी सूचियों को भी अवैध और अमान्य करार दिया गया है। दरअसल 5 मार्च, 2010 से 11 मई, 2012 तक जिन 42 वर्गों को ओबीसी प्रमाणपत्र दिए गए, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के उन आदेशों को भी रद्द कर दिया है। ममता बनर्जी मई, 2011 में सत्ता में आई थीं, लिहाजा उनके कार्यकाल में भी दिए गए ओबीसी प्रमाणपत्र 'असंवैधानिक' करार दे दिए गए हैं। यकीनन यह ममता सरकार के लिए गंभीर धक्का है। अदालत के फैसले से करीब 5 लाख ओबीसी प्रमाणपत्र निरस्त हुए हैं। हालांकि जो पहले ही ऐसे आरक्षण का लाभ ले चुके हैं अथवा नौकरियों, सेवाओं में कार्यरत हैं या भर्तियों में चयन हो चुका है, वे अदालत के फैसले से अप्रभावी रहेंगे। मार्च, 2010 से पहले भी ओबीसी के 66 वर्गों में जो वर्गीकृत किए जा चुके हैं, उनसे जुड़े सरकार के कार्यकारी आदेश में भी अदालत ने हस्तक्षेप नहीं किया है, क्योंकि जनहित याचिकाओं में उनकी पहचान और वर्गीकरण को चुनौती नहीं दी गई है। अलबत्ता उच्च अदालत का जो फैसला सार्वजनिक हुआ है, उसमें मुसलमानों के ओबीसी दर्जे और आरक्षण का कोई उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव-प्रचार में यह मुद्दा शिद्दत से उठाते रहे हैं कि कांग्रेस और 'इंडिया' गठबंधन के घटक दल वोट बैंक और मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते आए हैं।

अदालत का यह फैसला उनके गाल पर करारा तमाचा है। गृहमंत्री अमित शाह की टिप्पणी है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने वोट बैंक के लिए पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लूटना चाहती हैं और उसे मुस्लिम समुदाय को देना चाहती हैं। ममता बनर्जी सरकार ने बिना कोई उचित सर्वे किए 118 मुस्लिम वर्गों को ओबीसी बनाया और फिर आरक्षण भी दिया। उसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा जाति आयोग के अधिनियम, 1993 के तहत पिछड़ा आयोग की कोई सलाह भी नहीं ली, जबकि राज्य सरकार के लिए ऐसा करना बाध्यता है।'' बहरहाल यह अपनी-अपनी राजनीति है। अदालती फैसले में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि बंगाल में मुसलमानों या घुसपैठियों को ओबीसी का दर्जा दिया गया और फिर आरक्षण सुनिश्चित कर 'वोट बैंक' तैयार कर लिया गया। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की खंडपीठ के सामने यह मामला आया था, जिसमें ओबीसी के 77 समूहों की पहचान और वर्गीकरण को चुनौती दी गई थी। खंडपीठ ने कहा कि उन समुदायों का डाटा नहीं दिया गया, जिनके आधार पर बंगाल सरकार मानती है कि राज्य सरकार की सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। एक समुदाय को सिर्फ पिछड़ेपन के आधार पर ही ओबीसी घोषित नहीं किया जा सकता। वे वैज्ञानिक और पहचान योग्य डाटा के आधार पर ही ओबीसी में हैं। समुदायों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, जनसंख्या तथा अन्य अनारक्षित जमातों को भी शामिल करते हुए आकलन करना जरूरी है। खंडपीठ का यह भी मानना था कि ओबीसी के ऐसे प्रमाणपत्र पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई भी सलाह लिए बिना ही जारी किए गए। तृणमूल कांग्रेस के अभी तक के कार्यकाल में जितने भी ओबीसी प्रमाणपत्र दिए गए हैं, खंडपीठ ने सभी को अमान्य घोषित कर दिया है।

ओबीसी के 37 समुदायों के वर्गीकरण के संदर्भ में खंडपीठ ने 2012 के अधिनियम की धारा 16 को निरस्त कर दिया है। दरअसल यह धारा राज्य सरकार को शक्तियां देती है कि वह किसी भी अनुसूची में संशोधन कर सके। नतीजतन 37 समुदाय भी 2012 के अधिनियम की अनुसूची एक से बाहर कर दिए गए हैं। बहरहाल उच्च न्यायालय का निर्णय राजनीतिक, जातीय, सामाजिक दृष्टि से बेहद गंभीर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अदालत का यह फैसला मानने से इंकार कर दिया है।

editor@rokthoklekhaninews.com
+91 99877 75650
Faisal Shaikh @faisalrokthok

ROKTHOK LEKHANI NEWS
KHABREIN BE ROKTOK
Watch Us On YouTube
LIKE SHARE COMMENT SUBSCRIBE
youtube@rokthoklekhani

4 जून के बाद महाराष्ट्र पुलिस में बड़े फेरबदल...

मुंबई सीपी का भी होगा ट्रांसफर !

मुंबई: 4 जून को लेकर आम लोगों की उत्सुकता है कि देश में किसकी सरकार बनेगी? महाराष्ट्र में महायुति और महा विकास आघाडी में किसे लोकसभा में ज्यादा सीटें मिलेंगी। लेकिन पुलिस महकमे में इस बात को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि 4 जून के बाद महाराष्ट्र पुलिस में कुछ बड़े फेरबदल हो सकते हैं। सदानंद दाते के ठक्ख चीफ बनने के बाद महाराष्ट्र एटीएस चीफ की पोस्ट पिछले दो महीने से खाली पड़ी है। 4 जून के बाद ही महाराष्ट्र एटीएस को नया चीफ मिलेगा। फिलहाल आईजी रैंक के चंद्र किशोर मीणा के पास एटीएस चीफ का चार्ज है, जबकि एटीएस चीफ की पोस्ट अडिशनल डीजी रैंक की है। अडिशनल डीजी रैंक के निकित कौशिक और विश्वास नांगरे पाटील का नाम एटीएस चीफ की पोस्ट के लिए सबसे आगे चल रहा है। दोनों इन दिनों एसीबी में हैं। कौशिक ने अतीत में आईजी एटीएस के तौर पर काम किया है। वह लंबे समय तक मुंबई क्राइम ब्रांच में रहे। वहीं, विश्वास नांगरे पाटील ने मुंबई पुलिस में जॉइंट सीपी, लॉ ऐंड ऑर्डर के तौर पर लंबी पारी खेली है। मुंबई शहर में जब-तब ऑल आउट ऑपरेशन चलता रहता है, जिसमें काफी फरार आरोपियों को पकड़ा जाता था। यह आइडिया विश्वास नांगरे पाटील का था।

विवेक फणसलकर को मुंबई सीपी बने इस 30 जून को दो साल हो जाएंगे। अमूमन मुंबई सीपी का कार्यकाल दो साल का ही होता है। उनका मार्च, 2025 में रिटायरमेंट है। चूंकि रश्मि शुक्ला को पहले ही महाराष्ट्र डीजीपी का दो साल का फिक्स कार्यकाल दिए जाने की घोषणा की जा चुकी है, इसलिए देखने वाली बात होगी कि क्या विवेक फणसालकर मार्च, 2025 तक मुंबई सीपी के पद पर ही रहेंगे या उन्हें कहीं और शिफ्ट किया जाएगा? जयजीत सिंह के अप्रैल में रिटायरमेंट की वजह से महाराष्ट्र एसीबी के चीफ की पोस्ट भी इन दिनों खाली है। मुंबई सीपी की तरह एसीबी चीफ की पोस्ट भी डीजी रैंक में है। वैसे होमगार्ड और सिविल डिफेंस का चीफ भी डीजी रैंक का ही अधिकारी होता है। डॉक्टर भूषण उपाध्याय के रिटायरमेंट के बाद वह पद भी भरा जाना है। वैसे, अडिशनल डीजी, लॉ ऐंड ऑर्डर संजय सक्सेना ने मुंबई क्राइम ब्रांच चीफ के तौर पर लंबी पारी तो नहीं खेली, लेकिन उनका वहां ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा। अगर, उनका डीजी रैंक में प्रमोशन अभी दूर होगा, तो वह भी एटीएस चीफ की दौड़ में रहेंगे।

बीजेपी को पिछले दो लोकसभा चुनाव के मुकाबले कम सीटें मिलेंगी - पवार

मुंबई: महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव पांच चरणों में खत्म हो चुका है. अन्य राज्यों में अभी दो चरणों के लिए मतदान होना बाकी है. 2024 के चुनाव के बीच शरद पवार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है. एक इंटरव्यू में पवार ने कहा, ''केवल प्रधानमंत्री ही हैं जो राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं. इन्हें शहजादे आदि कहते हैं. प्रधानमंत्री के इस अपवाद को छोड़ दें तो राहुल गांधी को बहुसंख्यक लोग परिपक्व और गंभीर नेता मानते हैं.''

लोकसभा चुनाव के बीच शरद पवार ने दावा किया कि ''बीजेपी को पिछले दो लोकसभा चुनाव के मुकाबले कम सीटें मिलेंगी. अगर बीजेपी को बहुमत से कम सीटें मिलती हैं तो वे निश्चित रूप से देश में समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ लाकर देश को एक स्थिर सरकार देने की कोशिश करेंगे. पवार ने भरोसा जताते हुए कहा कि महाराष्ट्र में उनकी सीटें घट जाएंगी.''

यहां बता दें, महाराष्ट्र में हुए लोकसभा चुनाव 2019 शरद पवार की एनसीपी (अविभाजित) और कांग्रेस ने साथ मिलकर लड़ा था. पिछले लोकसभा चुनाव में दोनों ने केवल पांच सीटें जीतीं थी. पवार ने दावा किया कि इस बार वो सीटें बढ़ने वाली हैं. शरद पवार ने पिछले लोकसभा चुनाव का जिक्र कर कहा, महाराष्ट्र में 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली थी. इस वर्ष इसमें सुधार होगा. राजस्थान और गुजरात में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी, उन दोनों राज्यों में इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कुछ सीटें जरूर मिलेंगी. हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तीनों राज्यों में कांग्रेस की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा. पवार ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बीजेपी का ज्यादा प्रभाव नहीं है, इसलिए वहां उनके लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं है.

शरद पवार ने कहा, ''राहुल गांधी और उनका समर्थन करने वालों का रवैया बदल गया है. 2019 के बाद उन्होंने जो यात्राएं आदि कीं उन्हें उससे अच्छी प्रतिक्रिया मिली है. उनकी नेतृत्व शैली में कुछ अच्छे बदलाव आए हैं. राजनीति के प्रति राहुल गांधी का दृष्टिकोण अधिक गंभीर है. उन्होंने जो पदयात्रा की, लोगों से मुलाकात की, उसमें महिलाओं, युवाओं, बेरोजगारों, दलितों, किसानों से मुलाकात की. इससे पता चलता है कि वह राजनीति को लेकर गंभीर हैं.''

डॉक्टरों ने भीषण गर्मी में बच्चों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरे की चेतावनी दी

मुंबई: जैसे-जैसे देश में चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है और गर्म दिन भी आने लगे हैं, विशेषज्ञों ने बच्चों के लिए एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती की चेतावनी दी है - निर्जलीकरण, जो अक्सर दस्त से बढ़ जाता है, इस आयु वर्ग में मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण है। फिर भी, डॉक्टरों का कहना है कि ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट (ओआरएस), एक सरल लेकिन प्रभावी समाधान, काफी कम उपयोग किया जाता है। ओआरएस पसीने और दस्त के कारण खोए गए तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स की भरपाई करता है, जटिलताओं को रोकता है और तेजी से स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देता है, खासकर पांच साल से कम उम्र के बच्चों में। नानावती अस्पताल में बाल चिकित्सा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के निदेशक डॉ. विभोर बोरकर ने कहा, ''एक स्वस्थ शरीर प्रतिदिन पसीने, मूत्र और अपशिष्ट के माध्यम से लगभग 400 मिलीलीटर पानी खो देता है।'' उन्होंने कहा, ''इस पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसलिए इसकी पूर्ति के लिए केवल पानी पीना ही पर्याप्त नहीं है।''

ग्लेनीगल्स अस्पताल के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. ललित वर्मा ने कहा कि किसी को ओआरएस और वाणिज्यिक चीनी युक्त पेय के बीच अंतर जानना चाहिए। ''ये पेय कुछ हद तक इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन आवश्यक ग्लूकोज-सोडियम और पोटेशियम अनुपात की कमी रखते हैं।'' मधुमेह रोगी ओआरएस का उपयोग नियंत्रित तरीके से कर सकते हैं, लेकिन किडनी या विशेष समस्याओं वाले लोगों को डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। गोंद कतीरा पानी, जिसे ट्रैगैकैंथ गोंद के नाम से भी जाना जाता है, एस्ट्रैगलस गमिफर पेड़ के रस से प्राप्त एक प्राकृतिक उपचार है।

यह त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए जलयोजन, सूजन-रोधी गुण और एंटीऑक्सीडेंट जैसे सौंदर्य लाभ प्रदान करता है। जानें कि प्रोबायोटिक्स, आवश्यक पोषक तत्व और कम कैलोरी वाले दही आधारित पेय पाचन, वजन प्रबंधन और समग्र स्वास्थ्य में कैसे सहायता कर सकते हैं। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने श्रम विभाग से भीषण गर्मी के दौरान बाहरी काम को सीमित करने या मजदूरों के लिए इनडोर विकल्प प्रदान करने का आग्रह किया। भीषण गर्मी के कारण नोएडा और गाजियाबाद में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जिससे दैनिक गतिविधियों पर लू का असर दिख रहा है।

महाराष्ट्र में सियासी बदलाव पर टिकी है देश की नजर

मुंबई: शिवसेना और एनसीपी के बीच विभाजन के बाद राज्य में यह पहला बड़ा चुनाव है. इसलिए देश की नजर महाराष्ट्र में सियासी बदलाव पर टिकी है. इसमें अब मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव परिणाम की भविष्यवाणी की जाती है. सियासी रणभूमि में इस वक्त कई सीटों पर चुनावी नतीजों पर दांव चल रहा है. ऐसे में राजनीतिक नेता भी अपने अनुभव और विश्लेषण के आधार पर भविष्यवाणी कर रहे हैं कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी.

बहरहाल महायुति की टेंशन बढ़ गई है क्योंकि उनके ही महागठबंधन में शामिल पार्टी के नेता रामदास अठावले ने 35 से 40 सीटें जीतने की भविष्यवाणी की है. महाराष्ट्र में इस साल हुए लोकसभा चुनाव की भविष्यवाणी करना हर किसी के लिए मुश्किल हो गया है. इसलिए महाराष्ट्र में महागठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी इसका सही अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है. लेकिन, दोनों मोर्चों के नेताओं को भरोसा है कि वे सबसे ज्यादा सीटें जीतेंगे.

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव का सियासी गणित पेश करते हुए कहा, ''इस साल महाराष्ट्र में जबरदस्त टक्कर देखने को मिली है. मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में 35 से 40 सीटों पर महायुति की जीत होगी. दिलचस्प बात यह है कि कल ही राष्ट्रीय समाज पक्ष के प्रमुख महादेव जानकर ने अपना विश्वास जताया था कि महायुति को महाराष्ट्र में 42 सीटों पर जीत हासिल होगी.

महाराष्ट्र में 48 लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत ईवीएम में बंद हो गयी है. ऐसे में अब सभी नेताओं और कार्यकताओं को 4 जून के नतीजे का इंतजार है. महायुति नेता लगातार यह विश्वास जता रहे हैं कि वे 40 से ज्यादा सीटें जीतेंगे. खास तौर पर उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने भी विश्वास जताया है कि महागठबंधन उतनी ही सीटें जीतेगा जितनी पिछले चुनाव में जीती थी.

मुंबई और ठाणे में भीषण गर्मी... 45 के पार पहुंचा पारा

मुंबई : देश में मॉनसून जल्द दस्तक देगा मगर महाराष्ट्र के लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। मुंबई और ठाणे में भीषण गर्मी पड़ रही है। इस क्षेत्र के निवासियों को गर्मी की मार झेलना पड़ रहा है। मुंबई, ठाणे, पालघर जिलों गर्म और आर्द्र स्थितियों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि मुंबई और ठाणे में लू चलने की संभावना है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, अकोला में गुरुवार को अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो विदर्भ क्षेत्र (पूर्वी महाराष्ट्र) में सबसे अधिक है। इसके बाद यवतमाल (43.5), अमरावती (43.2), ब्रह्मपुरी (43.2), चंद्रपुर (43.2), वर्धा (43.2), गढ़चिरौली (42.6), बुलढाणा (42), वाशिम (42), नागपुर (41.9), गोंदिया (40.4) और भंडारा (40.2) रहा। आईएमडी नागपुर ने विज्ञप्ति में कहा कि अकोला और अमरावती में अगले पांच दिनों तक लू की स्थिति बने रहने की उम्मीद है।

चक्रवात रेमल का अलर्ट

मौसम विज्ञान केन्द्र (आईएमडी) की ओर से ओडिशा, गुजरात, पश्चिम बंगाल के साथ-साथ महाराष्ट्र के लिए चक्रवात 'रेमल' अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से पश्चिम बंगाल के शहर कोलकाता के कुछ हिस्सों में गुरुवार सुबह भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने बताया कि बुधवार को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य भाग पर बना निम्न दबाव क्षेत्र उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया और आज सुबह करीब 08:30 बजे बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य तथा उससे सटे दक्षिण भाग पर एक निम्न दबाव क्षेत्र के रूप में स्थापित हो गया। इसके उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते रहने और शुक्रवार सुबह तक बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर एक अवदाब में परिवर्तित होने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया, ''इसके उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ना जारी रखने के आसार हैं तथा शनिवार सुबह तक बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य भाग में चक्रवाती तूफान के रूप में बदल जाने का अनुमान है। साथ ही इसके उत्तर की ओर बढ़ने तथा 26 मई की शाम तक चक्रवाती तूफान के रूप में बंगलादेश और उससे सटे पश्चिम बंगाल के तटों के पास पहुंचने के आसार हैं।'' बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य भाग में बुधवार को कम दबाव का क्षेत्र बना था।

बांधों में सिर्फ 24 फीसदी स्टोरेज, पानी की गंभीर कमी

मुंबई: मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में भीषण गर्मी बढ़ती जा रही है। एक ओर जहां किसान सूखे से जूझ रहे हैं, वहीं राज्य के सामने पानी की कमी का भीषण संकट मंडरा रहा है। जल संसाधन विभाग ने बताया कि बुधवार को राज्य के सभी प्रमुख बांधों में महज 24.03 फीसदी पानी बचा है। छत्रपति संभाजीनगर में हालात बेहद खराब हैं। यहां बांधों में पानी का स्टोरेज महज 9.73 फीसदी रह गया है। यह भयावह हकीकत सामने आई है कि राज्य के करीब 10 हजार गांवों और घाटियों में टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है। जल संसाधन विभाग की ओर से 22 मई तक घोषित जल भंडार में कुल दो हजार 994 बांधों और जलाशय का पानी शामिल है। पिछले साल इसी दिन राज्य के बांधों में जल भंडारण 34.36 फीसदी था, लेकिन इस साल यह सीधे घटकर 24.03 फीसदी पर आ गया है। सबसे कम जल भंडारण छत्रपति संभाजीनगर में दर्ज किया गया है। यहां के कुल 920 बांधों और जलाशय में सिर्फ 9.73 फीसदी पानी बचा है। इसके बाद पुणे के कुल 720 बांधों और जलाशयों में से 18.18 फीसदी, नासिक के 537 में 26.34 फीसदी और कोंकण के 173 बांधों और जलाशयों में 37.41 फीसदी पानी है। नागपुर के 383 में से 38.88 फीसदी और अमरावती के 261 बांधों और जलाशय में 40.17 फीसदी भंडारण है।

कुल 3,622 टैंकरों से राज्य के अलग-अलग स्थानों पर पानी की सप्लाई की गई थी। दिनभर में यह संख्या 36 टैंकर बढ़कर सीधे 3 हजार 658 तक पहुंच गई। बुधवार को प्रदेश भर में तीन हजार 658 टैंकरों से पानी की सप्लाई की गई। इसमें 3 हजार 563 निजी और 95 सरकारी टैंकर शामिल हैं। यह बात सामने आई है कि सात हजार 623 वादियों और दो हजार 949 गांवों में टैंकरों से जलापूर्ति की जा रही है।

महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने बुधवार को मांग की कि पूरा राज्य सूखे से जूझ रहा है। अधिकांश क्षेत्रों में इसकी भारी कमी है। राज्य सरकार को अब सूखे पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। क्योंकि राज्य में लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं। बांध में पानी का भंडारण कम है और हजारों गांवों, महलों और बस्तियों को पीने का पानी नहीं मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि आचार संहिता में ढील देकर यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए कि पानी की कमी वाले हर गांव में पानी उपलब्ध हो और पशुओं के लिए चारा उपलब्ध हो। नासिक शहर के लिए गंगापुर, मुक्ने और दरना बांधों में 31 जुलाई तक पानी की सप्लाई नहीं होने के कारण प्रशासन ने आखिरकार अघोषित पानी कटौती शुरू कर दी है।

राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से आचार संहिता में राहत मांगी...

मुंबई : महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर चुनाव खत्म होने के बाद राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से आचार संहिता में राहत मांगी है। उसके लिए राज्य के मुख्य सचिव नितिन करीर ने बुधवार को चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है आचार संहिता के चलते सरकार बेमौसम बारिश की मार झेल रहे किसानों की मदद नहीं कर पा रही है। रुकी परियोजनाओं को गति नहीं मिल पा रही है। साथ ही पानी की कमी से जूझ रहे ग्रामीणों को पानी सप्लाई नहीं कर पा रही है। आचार संहिता के चलते महानगरपालिका, नगरपालिका के काम प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए चुनाव आयोग महाराष्ट्र को आचार संहिता में राहत दें। इधर, विपक्ष सरकार पर लगातार हमले बोल रही है। किसानों को मदद नहीं करने, गांवों तक पानी नहीं पहुंचाने का आरोप लगा रही है।

महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के लिए पांच अलग-अलग चरणों में मतदान हो गया है। देश के अलग-अलग हिस्सों में अभी भी चुनाव प्रचार चल रहे हैं। अभी 25 मई और 1 जून को मतदान होना है। मतदान के बाद 4 जून को मतगणना शुरू होगी। इससे चलते देशभर में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। महाराष्ट्र में चुनाव खत्म हो गए हैं। ऐसे में राज्य सरकार चुनाव संहिता में चुनाव आयोग से ढिलाई चाहती है, ताकि सरकार पीड़ित और सरकारी सुविधा और मदद के लिए जूझ रहे लोगों की मदद कर सके। मुख्य सचिव ने लिखे पत्र में चुनाव आयोग का ध्यान खींचा है।

इधर, आसमान में बादल घिरने लगे हैं। मॉनसून आहट देने लगी है। राज्य में कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉजेक्ट चल रहे हैं जिनको गति देने की आवश्यकता है। उसके लिए फंड ट्रांसफर करने पड़ेंगे। आचार संहिता के चलते सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है। इसके अलावा स्थानीय निकायों में कामकाज ठप है। जो काम चल रहे हैं, उसके मॉनूसन से पहले पूरा करना है। आमतौर पर मॉनसून में ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम बंद रहते हैं।

क्या कहता है चुनाव आचार संहिता का नियम?

चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है और नई संसद की स्थापना तक आचार संहिता लागू रहती है। इस दरमियान किसी भी प्रकार की कोई नई घोषणा कोई भी सरकार नहीं कर सकती। लोकसभा के चुनाव नतीजे 4 जून को आएंगे। चुनाव नतीजे आने के 8 से 10 दिन में नई सरकार बनेगी। आचार संहिता के चलते सरकार का कामकाज पूरी तरह से ठप है। माना जा रहा है कि मुख्य सचिव के पत्र के बाद आचार संहिता की पाबंदियों से कुछ राहत मिल सकती है।

आचार संहिता के कारण मॉनसून सत्र टलेगा!

महाराष्ट्र विधानमंडल का मॉनसून सत्र 10 जून से शुरू होने वाला है, लेकिन इसे एक या दो सप्ताह के लिए टाला जा सकता है। सत्र की तारीख आगे बढ़ाने के लिए 21 मई को महाराष्ट्र विधान मंडल कामकाज समिति की बैठक होने वाली थी, लेकिन उसे भी टाल दिया गया। अब कहा जा रहा है कि 4 जून को लोकसभा के चुनाव नतीजे आने के बाद ही कामकाज समिति की बैठक होगी। इस सत्र में शिंदे सरकार बजट पेश करने वाली है, इसलिए माना जा रहा है कि मॉनसून सत्र तीन सप्ताह का होगा।

चुनाव रिजल्ट से पहले भिवंडी में फूटी अजित पवार की एनसीपी

मुंबई : भिवंडी में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान तो हो गया है, लेकिन परिणाम आने से पहले ही इंडिया गठबंधन के स्थानीय नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया है। शहर के दो प्रमुख नेताओं पर शहर का माहौल खराब करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भिवंडी शहर एनसीपी के जिलाध्यक्ष शोयेब खान गुड्डू ने भिवंडी पूर्व के सपा विधायक रईस शेख और भिवंडी शहर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन के खिलाफ आरोप लगाया है कि इन नेताओं की हठधर्मिता के कारण लोकसभा चुनाव में मतदान काफी कम हुआ है। शोयेब के इस बयान पर रईस शेख ने कहा है कि इस मुद्दे पर पूर्व मंत्री जितेंद्र अव्हाड और महाविकास अघाडी के प्रत्याशी सुरेश म्हात्रे बाल्या मामा ध्यान देंगे। शेख ने कहा है कि अपने स्तर के नेताओं के बयान पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत है। वहीं, मोमिन ने कहा है कि इसकी शिकायत वह प्रदेश कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं से करेंगे। भिवंडी लोकसभा चुनाव के दौरान भिवंडी पूर्व में शेख, पश्चिम में मोमिन और भिवंडी ग्रामीण में शिवसेना भिवंडी लोकसभा संपर्क प्रमुख और पूर्व विधायक रूपेश म्हात्रे को जिम्मेदारी दी गई थी।

बांद्रा स्काईवॉक को तोड़ने का काम फिर से शुरू...

मुंबई : रेलवे स्टेशन से एसवी रोड पर लकी जंक्शन तक स्काईवॉक को तोड़ने का काम फिर से शुरू होने वाला है। मेट्रो लाइन 2बी (डीएन नगर से मांडले) के लिए रास्ता बनाने के लिए स्काईवॉक का एक बड़ा हिस्सा लगभग सात महीने पहले ही तोड़ दिया गया था। जबकि स्काईवॉक के किनारों पर सुरक्षा कवर हटा दिया गया था, खंभे, वॉकवे और उसके चारों ओर धातु की छड़ें बनी रहीं। बांद्रा स्टेशन को बहाल कर दिया गया है और उसकी सुंदर स्थिति में लौटा दिया गया है, ''क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक आशीष शेलार ने कहा।

''स्टेशन पर यातायात को सुव्यवस्थित करने पर भी काम किया गया है। स्काईवॉक का केवल दृश्य ही बचा है, जिसके खंभे जमीन पर पैदल यात्रियों की आवाजाही में बाधा डाल रहे हैं। इसे हटा दिया जाएगा।'' शेलार ने कहा कि स्काईवॉक को मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमएमआरडीए) से बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को स्थानांतरित कर दिया गया था, जो स्काईवॉक को ध्वस्त कर रहा है।

उन्होंने कहा, ''अगर स्काईवॉक का उपयोग नहीं किया जा रहा है, और शेष हिस्से का उपयोग नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है, तो बेहतर है कि यह बिल्कुल न रहे।'' ''यह आकाश के दृश्य को अवरुद्ध कर रहा है। इसके चले जाने से, बांद्रा स्टेशन के दृश्य खुल

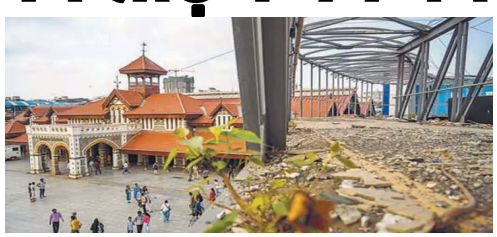

जाएंगे।'' शेलार ने स्काईवॉक को तोड़ने का काम फिर से शुरू करने का संकेत देने के लिए बांद्रा स्टेशन के बगल में स्थित मस्जिद के इमाम को नारियल तोड़ने के लिए आमंत्रित किया।

''जब लोग यहां ऊपर की मंजिलों पर स्थित मस्जिद में प्रार्थना करने आते हैं, तो उनका स्वागत वहां लेटे हुए पुरुषों और महिलाओं के दृश्य से किया जाता है, जो धूम्रपान कर रहे हैं और नशीली दवाएं ले रहे हैं। कुछ समय से हमारी शिकायत रही है कि इसे हटा दिया जाना चाहिए, इसलिए हमें खुशी है कि शेलार ने इसे उठाया है, '' इमाम तौहीद अख्तर सिद्दीकी ने कहा।

हालाँकि, अन्य लोग निराश थे कि स्काईवॉक हमेशा के लिए दूर जा रहा था। बांद्रा पश्चिम के पूर्व नगर निगम पार्षद राजा रहेबर खान ने स्काईवॉक के टूटने के कारण पैदल यात्रियों को होने वाली समस्याओं पर चर्चा की। ''स्काईवॉक का बड़ा हिस्सा 7-8 महीने पहले तोड़ दिया गया था क्योंकि यह मेट्रो लाइन निर्माण के रास्ते में था। मैंने यह भी प्रस्ताव दिया कि इस स्काईवॉक के प्रमुख हिस्सों में एस्केलेटर बनाए जाएं ताकि सभी प्रकार के पैदल यात्रियों के लिए चलना आसान हो सके। यहां मंदिर, नगरपालिका स्कूल और मस्जिद हैं, जिनके लिए लोग स्काईवॉक का इस्तेमाल करते थे क्योंकि नीचे की सड़क संकरी है। और अब, निस्संदेह, यह स्काईवॉक के बिना पैदल चलने वालों के बीच अराजकता पैदा करने वाला है।

शास्त्री नगर के निवासी संजय भोंडीराम मगरे ने कहा, ''मैं नियमित रूप से उस स्काईवॉक से आवागमन करता था। बच्चे इसका इस्तेमाल अपने स्कूल जाने के लिए भी करते थे. अब, मानसून करीब आ रहा है और स्काईवॉक के नीचे इस संकरी सड़क पर अराजकता होने वाली है क्योंकि पैदल यात्री और वाहन दोनों सड़क का उपयोग करेंगे। सिग्नल पार करने के लिए कम से कम 15 मिनट तक इंतजार करना पड़ता है। यदि स्काईवॉक मौजूद होता, तो लोग सड़क पर वाहनों से सावधान रहने के बजाय शांति से उस पर चल सकते थे।

अंबादास दानवे ने एकनाथ शिंदे-भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया राज्य ने एक और बड़ी परियोजना खो दी

मुंबईः विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने एकनाथ शिंदे-भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि महाराष्ट्र ने भाजपा सरकार वाले राज्य के हाथों एक और बड़ी परियोजना खो दी है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा मप्र में ईथेन क्रैकिंग यूनिट स्थापित करने की योजना के बारे में रिपोर्टों का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि 50,000 करोड़ रुपये की पीएसयू परियोजना छत्रपति संभाजीनगर या रत्नागिरी के दाभोल में प्रस्तावित थी, चैतन्य मारपकवार की रिपोर्ट उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ''प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश को कैसे

मिला...? रोजगार में महाराष्ट्र का हिस्सा इतनी आसानी से कैसे चला गया? जवाब दें उद्योग मंत्री उदय सामंत।'' बीजद ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में परिक्रमा परियोजना का राजनीतिकरण करने के लिए भाजपा की आलोचना की और भाजपा पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। बीजद के बेरहामपुर सांसद उम्मीदवार ने भाजपा के 4,500 करोड़ रुपये खर्च करने के दावे का खंडन करते हुए कहा कि सरकार ने परियोजना के लिए 325 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

शरद पवार ने लोकसभा चुनाव के लिए नई पार्टी इंडिया ब्लॉक बनाई, जो चमत्कार दिखाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक साक्षात्कार में, उन्होंने शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के साथ एमवीए की प्राथमिकताओं और भविष्य पर चर्चा की। लौटोलिम के ग्रामीणों ने आजीविका के लिए कृषि पर निर्भरता का हवाला देते हुए, बोरिम पुल के लिए धान के खेतों के अधिग्रहण की सरकार की योजना का विरोध किया।

मुंबई उपनगर के एन वार्ड, एस वार्ड और टी वार्ड के हिस्सों में आज से 24 घंटे की पानी की कटौती

मुंबई : मुंबई उपनगर के कई हिस्सों में आज (24 मई) से 24 घंटे की पानी की कटौती हो रही है। बृहन्मुंबई महानगरपालिक (बीएमसी) ने बताया कि पूर्वी उपनगरों में तीन नगरपालिका वार्डों में शुक्रवार और शनिवार के बीच 24 घंटे पानी की कटौती होगी। बीएमसी के मुताबिक, शहर के एन वार्ड, एस वार्ड और टी वार्ड के कुछ हिस्सों में 24 मई से 25 मई तक 24 घंटे तक जल आपूर्ति बंद रहेगी।

बीएमसी अधिकारियों ने कहा कि गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड (जीएमएलआर) के चल रहे निर्माण के कारण मौजूदा 1,200 मिमी पाइपलाइन को मोड़ने का काम किया जा रहा है। यह पाइपलाइन वर्तमान में टी-वार्ड के मुलुंड इलाके में स्थित

है। एक अधिकारी के मुताबिक, पाइपलाइन का डायवर्जन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वर्तमान में उस स्थान पर स्थित है जहां प्रस्तावित जीएमएलआर कॉरिडोर के फ्लाईओवर के लिए नींव बनाई जाएगी। पाइपलाइन के डायवर्जन का काम शुक्रवार को सुबह 11.30 बजे के आसपास शुरू किया गया, जो अगले दिन यानी शनिवार सुबह 11.30 बजे तक पूरा होने की उम्मीद है। इस काम के दौरान पानी की बबार्दी नहीं हो, इसलिए पानी की आपूर्ति रोकी जाएगी। जिसके चलते मुंबई के टी-वार्ड (मुलुंड) के अलावा, एस-वार्ड (भांडुप, कांजुरमार्ग, विक्रोली) और एन-वार्ड (घाटकोपर) में पानी की आपूर्ति 24 घंटे के लिए प्रभावित रहेगी।

समृद्धि एक्सप्रेसवे को चंद्रपुर, गोंदिया और गढ़चिरौली के अविकसित जिले तक राजमार्ग के विस्तार पर काम शुरू

नागपुरः राज्य भर में कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने समृद्धि एक्सप्रेसवे को चंद्रपुर, गोंदिया और गढ़चिरौली के अविकसित जिले तक विस्तारित करने की अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। इस पहल का लक्ष्य लगभग -60,000 करोड़ के अनुमानित निवेश के साथ 12 जिलों को भारत के सबसे लंबे और उच्चतम पहुंच-नियंत्रित राजमार्ग से जोड़ना है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने

11 दिसंबर, 2022 को नागपुर में एक्सप्रेसवे के पहले चरण के उद्घाटन के दौरान समृद्धि का विस्तार करने की योजना का अनावरण किया था। अब, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) ने छह ग्रीनफील्ड एक्सेस-नियंत्रित एक्सप्रेसवे के लिए वित्तीय बोलियां खोलकर प्रक्रिया शुरू की है। इनमें नागपुर-चंद्रपुर एक्सप्रेसवे, भंडारा-गढ़चिरौली और नागपुर-गोंदिया मार्ग शामिल हैं। एमएसआरडीसी के प्रबंध निदेशक अनिल गायकवाड़ के अनुसार, परियोजना में अन्य तीन एक्सप्रेसवे में पुणे रिंग रोड, विरार और अलीबाग के बीच एक मल्टी-मॉडल कॉरिडोर और जालना को नांदेड़ से जोड़ने वाला एक अन्य एक्सप्रेसवे शामिल है। उन्होंने टीओआई को बताया, ''भूमि अधिग्रहण और अन्य संबंधित लागतों के अतिरिक्त खर्च के साथ, इन छह परियोजनाओं की नागरिक लागत लगभग -89,000 करोड़ होने का अनुमान है।''

बेमौसम बारिश से माथेरान हिल स्टेशन में जल संकट पैदा हो गया

नवी मुंबई : माथेरान हिल स्टेशन लगभग एक सप्ताह से पानी की कमी से जूझ रहा है, तेज हवाओं के साथ बेमौसम बारिश के बाद कर्जत तालुका में लगभग 70 बिजली के खंभे झुक गए और उखड़ गए। अधिकांश पोल नेरल के निकट एक फीडर स्टेशन से जुड़ते हैं। बिजली आपूर्ति बंद होने से, उल्हास नदी और हिल स्टेशन पर चार्लोट झील पर निस्पंदन संयंत्र से पानी की निकासी और आपूर्ति प्रभावित हुई है। हिल स्टेशन पर जनरेटर भी खराब है। कार्यकर्ता जनार्दन पार्टे ने कहा, ''नागरिक निकाय ने 10'५ जनरेटर खरीदा लेकिन कभी उसका रखरखाव नहीं किया। कर्जत तालुका में पिछले सप्ताह 13 और 14 मई को दो दिनों तक तूफान आया था। मौसम की स्थिति के कारण घरों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। बिजली के खंभों के बीच लटकते बिजली सप्लाई के तारों पर पेड़ गिर गये. अधिकारियों को चरणबद्ध तरीके से बिजली आपूर्ति बहाल करने में कुछ दिन लगे।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। मोबाइल नं 998777 5650, Email-editor@rokthoklekhaninews.com